

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1767 / 2013 / कोटा.

मैसर्स एस.डी.इण्डस्ट्रीज, भामाशाह मण्डी, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

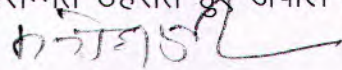
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 09 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 14 / सीएसटी / 12-13 / कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुते की गई है। अपीलीय अधिकारी उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 33 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.06.2012 के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन प्रस्तुत घोषणा पत्र 'सी' रूपये 22,58,241/- को कर निर्धारण सम्पूरित करने के पश्चात प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार कर दिया, के सम्बन्ध में अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण दिनांक 31.01.2012 को पूर्ण किया जा चुका था। दिनांक 29.03.2012 को व्यवहारी ने अप्रस्तुत 'सी' फॉर्म राशि रूपये 22,58,241/- को प्रस्तुत करते हुए संशोधन प्रार्थना-पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये। व्यवहारी ने घोषणा पत्र 'सी', क्रेता व्यवहारी द्वारा समय पर नहीं दिये जाने के कारण विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण बताया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा पत्र 'सी' को स्वीकार नहीं करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किया। अपीलीय अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12(7) में दिनांक 01.10.2005 को किये गये संशोधन के अनुसार प्रत्येक तिमाही समाप्ति से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत ठहराते हुए अपील अस्वीकार की गई।



लगातार.....2



3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :-

- A. (2015) 12 RGSTR 170 (RTB-DB) M/s Buge India Ltd., Bundi v/s Commercial Taxes Officer, Bundi Appeal No. 1343/2009, Bundi Dated 15.05.2015
- B. (2015) 12 RGSTR 325 (RTB-SB) M/s Toshniwal Instruments Manufacturing Ltd., (Gangwana ) Ajmer v/s Appellate Authority, Ajmer & Commercial Taxes Officer, Special Circle, Ajmer Appeal No. 381/2014/Ajmer Dated 24.08.2015
- C. (2014) 9 RGSTR 69 M/s Laxmi Chemicals, Gotta, Nagaur v/s Commercial Taxes Officer, Nagaur Appeal No. 1527 to 1531, 1734 to 1736/2013/Nagaur Dated 01.01.2014

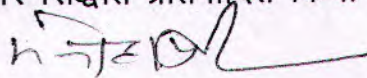
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया की घोषणा पत्र 'सी' हमेशा अन्य राज्य के क्रेता द्वारा दिये जाने पर प्रस्तुत किया जाता है। क्रेता व्यवहारी द्वारा समय पर घोषणा-पत्र नहीं दिये जाने के कारण इनकी प्रस्तुती में विलम्ब हुआ था। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है की कर निर्धारण वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण दिनांक 30.01.2012 को सम्पूरित होने के पश्चात दिनांक 05.06.2012 को अप्रस्तुत घोषणा-पत्र 'सी' राशि रूपये 22,58,241/- को प्रस्तुत करते हुए मांग में कमी करने के लिए कर निर्धारण आदेश को संशोधित करने की प्रार्थना की गई।

6. राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के द्वारा मैसर्स लक्ष्मी कैमिकल्स गोटन, नागौर निर्णय दिनांक 01.01.2014 के मामले में दिये गये निर्णय के अंश निम्न प्रकार हैं -

“इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्शन लि., 1994 एस.टी.सी. 410 में घोषणा प्ररूप की प्रस्तुत में हुयी देरी के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-



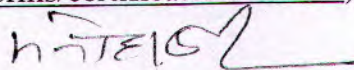
लगातार.....3



".....The aforesaid observations show that the mere use of the words "the first assessing authority" in sub-rule (7) of Rule 12 cannot and does not mean, in the context and scheme of the enactments concerned herein, that the appellate authorities do not have the power to receive Form-C in appeal. This power can of course be exercised only where sufficient cause is shown by the dealer for not filing them up to the time of assessment before the first assessing authority. If in a given case, a dealer had obtained further time from the first assessing authority and yet failed to produce them before him, it is obvious that the appellate authority would adopt a stiffer stand in judging the sufficient cause shown by the dealer for not producing them earlier. It is necessary to reiterate that receipt of those forms in appeal cannot be a matter of course; it should be allowed only where sufficient cause is established by the dealer for not producing them before the first assessing authority as contemplated by Rule 12(7). The requirement of the said sub-rule cannot be excluded consideration by the appellate court, while judging the sufficiency of the cause shown. It must be remembered that it is the primary obligation of the dealer and his failure to abide by it must be properly explained."

इसी क्रम में दिनांक 23.01.2015 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर, अवर अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व अन्य बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. व अन्य 142 एस.टी.सी. 1, के आलोक में, घोषणा प्ररूप की प्रस्तुती के संबंध में इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि -

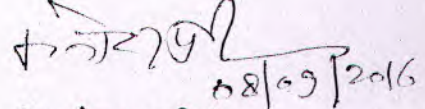
("The declaration forms/certificates are proof for concessional rate of tax and are required to assess the dealer at the applicable rate of tax at the time of assessment. In view of the above mentioned Hon'ble Supreme Court judgement. it is directed that if a dealer submits declaration forms/certificates, even after the stipulated period along with an application mentioning the cause for delay, the Assessing Authority should accept it after ascertaining that the dealer was prevented by a sufficient cause for not furnishing the declaration forms/certificates in time.")



लगातार.....4



7. हस्तगत प्रकरण के तथ्य उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के तथ्यों से पूर्णतः आच्छादित है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण समाधान कारक पाया जाता है। उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र 'सी' की नियमानुसार जांच कर आरोपित कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों में कमी करें।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपर्युक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।
9. निर्णय सुनाया गया।

  
08/09/2016  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य